

# RJS PRE Exam Preparation: Important Case Laws in Mohammedan Law

## I. विवाह (Marriage)

\* अब्दुल कादर बनाम सलीमा (Abdul Kadir v. Salima) (1886) ILR 8 All 149

\* मुख्य मुद्दा (Key Issue): मुस्लिम विवाह की प्रकृति (क्या यह एक धार्मिक संस्कार है या नागरिक अनुबंध)। (Nature of Muslim Marriage (whether it is a sacrament or a civil contract).)

\* निर्णय (Decision): इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने माना कि मुस्लिम विवाह एक "सिविल अनुबंध" है न कि केवल एक धार्मिक संस्कार, हालांकि इसमें धार्मिक तत्व भी शामिल होते हैं। यह विवाह के अनुबंधात्मक पहलू को रेखांकित करता है। (The Allahabad High Court held that Muslim marriage is a "civil contract" and not merely a religious sacrament, though it involves religious elements. This underscores the contractual aspect of marriage.)

\* खुरशीद बी बनाम मोहम्मद हुसैन (Khurshid Bibi v. Mohammad Hussain) (PLD 1967 Lah 100)

\* मुख्य मुद्दा (Key Issue): शादी के अनुबंध का गठन। (Formation of the marriage contract.)

\* निर्णय (Decision): इस मामले में "इजाब" (प्रस्ताव) और "कुबूल" (स्वीकृति) के महत्व पर जोर दिया गया है, जो मुस्लिम विवाह के वैध गठन के लिए आवश्यक हैं। (This case emphasizes the importance of "Ijab" (offer) and "Qabool" (acceptance) for the valid formation of a Muslim marriage.)

## II. मेहर/दहेज़ (Dower/Mahr)

\* अबीदुननिसा बेगम बनाम मुहम्मद फजल हुसैन (Abidunnisa Begum v. Mohammad Fazal Hussain) (1975) 1 APLJ 171

\* मुख्य मुद्दा (Key Issue): मेहर की प्रकृति और पत्नी का उस पर अधिकार। (Nature of Mahr and wife's right to it.)

\* निर्णय (Decision): यह स्पष्ट किया गया कि मेहर पति की ओर से पत्नी को विवाह के प्रति सम्मान के रूप में एक अनिवार्य भुगतान है और यह पत्नी का पूर्ण अधिकार है। (It was clarified that Mahr is a mandatory payment from the husband to the wife in consideration of the marriage and is the absolute right of the wife.)

\* हुसैनी बेगम बनाम मोहम्मद रसूल (Hussaini Begam v. Mohammad Rasul) (AIR 1928 Lah 178)

\* मुख्य मुद्दा (Key Issue): मेहर का भुगतान और जब यह देय होता है। (Payment of Mahr and when it becomes due.)

\* निर्णय (Decision): मेहर के भुगतान को लेकर स्थिति स्पष्ट की गई, जिसमें 'प्रॉम्प्ट मेहर' (तत्काल देय) और 'डेफर्ड मेहर' (स्थगित मेहर) की अवधारणाओं पर प्रकाश डाला गया। (The position regarding Mahr payment was clarified, shedding light on the concepts of 'prompt Mahr' (immediately due) and 'deferred Mahr' (postponed Mahr).)

### III. तलाक (Divorce)

\* मोहम्मद अहमद खान बनाम शाह बानो बेगम (Mohd. Ahmed Khan v. Shah Bano Begum) (1985 AIR 945)

\* मुख्य मुद्दा (Key Issue): तलाकशुदा मुस्लिम महिला का भरण-पोषण का अधिकार। (Right to maintenance of a divorced Muslim woman.)

\* निर्णय (Decision): सुप्रीम कोर्ट ने CrPC की धारा 125 के तहत भरण-पोषण के अधिकार को इद्दत अवधि के बाद भी मान्य किया। (The Supreme Court validated the right to maintenance under Section 125 of CrPC even after the iddat period.)

\* डेनियल लतीफी बनाम भारत संघ (Danial Latifi v. Union of India) (AIR 2001 SC 3958)

\* मुख्य मुद्दा (Key Issue): मुस्लिम महिला (तलाक पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 1986 की संवैधानिकता और उसकी व्याख्या। (Constitutionality and interpretation of the Muslim Women (Protection of Rights on Divorce) Act, 1986.)

\* निर्णय (Decision): सुप्रीम कोर्ट ने 1986 के अधिनियम को संवैधानिक ठहराया, लेकिन यह स्पष्ट किया कि पति की जिम्मेदारी इद्दत के बाद भी उचित और पर्याप्त भरण-पोषण प्रदान करने की है। (The Supreme Court upheld the 1986 Act but clarified that the husband's liability extends to providing fair and reasonable maintenance even after iddat.)

\* शायरा बानो बनाम भारत संघ (Shayara Bano v. Union of India) (AIR 2017 SC 4609)

\* मुख्य मुद्दा (Key Issue): 'तीन तलाक' (तलाक-ए-बिद्दत) की संवैधानिक वैधता। (Constitutional validity of 'triple talaq' (talaq-e-biddat).)

\* निर्णय (Decision): सुप्रीम कोर्ट ने 'तीन तलाक' की प्रथा को असंवैधानिक घोषित किया। (The Supreme Court declared the practice of 'triple talaq' unconstitutional.)

\* शमीम आरा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (Shamim Ara v. State of Uttar Pradesh) (AIR 2002 SC 3550)

\* मुख्य मुद्दा (Key Issue): तलाक की घोषणा और उसके प्रमाण का तरीका। (Manner of pronouncement and proof of divorce.)

\* निर्णय (Decision): सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि तलाक केवल पति द्वारा मनमाने ढंग से घोषित करने से प्रभावी नहीं होता; इसमें उचित प्रक्रिया और कारण होने चाहिए। (The Supreme Court clarified that talaq does not become effective merely by an arbitrary pronouncement by the husband; it must have a reasonable cause and follow due process.)

\* फतमा बी बनाम मोहम्मद जकारिया (Fatma Bibi v. Mohammad Zakaria) (AIR 1928 Cal 303)

\* मुख्य मुद्दा (Key Issue): खुल्अ तलाक (खुला) - पत्नी के पहल पर तलाक। (Khula divorce - divorce at the instance of the wife.)

\* निर्णय (Decision): इस मामले में खुल्अ तलाक के सिद्धांतों पर चर्चा की गई, जहां पत्नी पति को मेहर या अन्य लाभों के बदले तलाक ले सकती है, लेकिन इसके लिए पति की सहमति आवश्यक है। (This case discussed the principles of Khula divorce, where a wife can seek divorce in return for foregoing mahr or other benefits, but it requires the husband's consent.)

\* युसुफ बनाम सईदा (Yusuf v. Saeeda) (AIR 1952 All 35)

\* मुख्य मुद्दा (Key Issue): इद्दत की अवधि और उसके प्रभाव। (Period of Iddat and its implications.)

\* निर्णय (Decision): यह स्पष्ट किया गया कि इद्दत की अवधि तलाक के बाद अनिवार्य है ताकि पितृत्व के संबंध में किसी भी संदेह को दूर किया जा सके और पत्नी को फिर से शादी करने से पहले पर्याप्त समय मिल सके। (It was clarified that the period of Iddat is mandatory after divorce to remove any doubt regarding paternity and to allow the wife sufficient time before remarrying.)

#### IV. भरण-पोषण (Maintenance)

\* बद्रुद्दीन बनाम आयेशा बेगम (Badruddin v. Ayesha Begum) (1987 (1) DMC 142)

\* मुख्य मुद्दा (Key Issue): भरण-पोषण की देयता और पति की क्षमता। (Liability of maintenance and husband's capacity.)

\* निर्णय (Decision): यह मामला इस बात पर जोर देता है कि पति की आय और क्षमता के अनुसार पत्नी और बच्चों को उचित भरण-पोषण प्रदान किया जाना चाहिए। (This case emphasizes that wives and children should be provided reasonable maintenance according to the husband's income and capacity.)

\* नूर सबा खातून बनाम मोहम्मद कासिम (Noor Saba Khatoon v. Mohd. Quasim) (AIR 1997 SC 3280)

\* मुख्य मुद्दा (Key Issue): तलाकशुदा मुस्लिम महिला के बच्चों के भरण-पोषण का अधिकार। (Right to maintenance of children of a divorced Muslim woman.)

\* निर्णय (Decision): सुप्रीम कोर्ट ने CrPC की धारा 125 के तहत नाबालिग बच्चों के भरण-पोषण के लिए मुस्लिम पिता की निरंतर देयता को बरकरार रखा। (The Supreme Court upheld the continuous liability of a Muslim father to maintain his minor children under Section 125 of CrPC.)

#### V. वक्फ (Waqf)

\* फातिमा बी बनाम फातिमा बेगम (Fathima Bee v. Fathima Begum) (AIR 1957 Mad 330)

\* मुख्य मुद्दा (Key Issue): वक्फ का गठन और उसकी अनिवार्यताएं। (Formation of Waqf and its essentials.)

\* निर्णय (Decision): यह मामला वक्फ के वैध गठन के लिए आवश्यक तत्वों पर प्रकाश डालता है, जैसे कि संपत्ति का स्थायी विनियोजन, अल्लाह के नाम पर समर्पण और किसी धर्मार्थ या धार्मिक उद्देश्य के लिए। (This case sheds light on the essential elements for a valid Waqf formation, such as permanent dedication of property, dedication in the name of Allah, and for a charitable or religious purpose.)

\* मोहम्मद इलियास बनाम कौशर जहाँ (Mohd. Illias v. Kausar Jahan) (AIR 1980 SC 1104)

\* मुख्य मुद्दा (Key Issue): वक्फ की संपत्ति का प्रबंधन और उसके दुरुपयोग पर रोक। (Management of Waqf property and prevention of its misuse.)

\* निर्णय (Decision): यह निर्णय वक्फ संपत्तियों के उचित प्रबंधन और उनकी रक्षा के महत्व को रेखांकित करता है ताकि वक्फ के मूल उद्देश्य को पूरा किया जा सके। (This judgment underscores the importance of proper management and protection of Waqf properties to fulfill the original objective of the Waqf.)

#### VI. संरक्षकता (Guardianship)

\* गीता हरिहरन बनाम भारतीय रिजर्व बैंक (Githa Hariharan v. Reserve Bank of India) (AIR 1999 SC 1149)

\* मुख्य मुद्दा (Key Issue): प्राकृतिक अभिभावक के रूप में माता का अधिकार। (Mother's right as a natural guardian.)

\* निर्णय (Decision): हालांकि यह मामला मुख्य रूप से हिंदू कानून से संबंधित था, इसने सामान्य रूप से माता के अधिकारों को मजबूत किया और कानूनी अभिभावक के रूप में पिता की अनुपस्थिति में या अक्षमता की स्थिति में माता के अधिकारों को मान्यता दी, जिसके मुस्लिम कानून पर भी निहितार्थ थे। (Although this case primarily dealt with Hindu law, it generally strengthened mothers' rights and recognized their rights as legal guardians in the father's absence or incapacity, with implications for Muslim law as well.)

\* फिदा हुसैन बनाम नजीर हुसैन (Fida Hussain v. Nazir Hussain) (AIR 1957 All 409)

\* मुख्य मुद्दा (Key Issue): बच्चों की कस्टडी (हिज़ानत)। (Custody of children (Hizanat).)

\* निर्णय (Decision): इस मामले में हिज़ानत के सिद्धांतों पर चर्चा की गई है, जिसमें यह तय किया जाता है कि एक निश्चित उम्र तक बच्चों की कस्टडी किसके पास रहेगी (आमतौर पर मां के पास कुछ शर्तों के तहत)। (This case discusses the principles of Hizanat, which determines who retains custody of children up to a certain age (usually the mother under certain conditions).)

## VII. उपहार (Gifts - Hiba)

\* चंद पीर बनाम फातिमा (Chand Peer v. Fatima) (AIR 1957 AP 57)

\* मुख्य मुद्दा (Key Issue): वैध मुस्लिम उपहार (हिबा) के आवश्यक तत्व। (Essential elements of a valid Muslim gift (Hiba).)

\* निर्णय (Decision): इस मामले में यह स्थापित किया गया कि मुस्लिम उपहार के लिए तीन आवश्यक तत्व हैं: दाता द्वारा घोषणा (Declaration by the donor), ग्रहीता द्वारा स्वीकृति (Acceptance by the donee), और कब्जे का हस्तांतरण (Delivery of possession)। (This case established that there are three essential elements for a valid Muslim gift: Declaration by the donor, Acceptance by the donee, and Delivery of possession.)

\* कुरेशी बनाम रशीद (Qureshi v. Rasheed) (AIR 1999 MP 114)

\* मुख्य मुद्दा (Key Issue): हिबा का रद्दकरण (रिवोकेशन)। (Revocation of Hiba.)

\* निर्णय (Decision): यह स्पष्ट किया गया कि एक बार कब्जे का हस्तांतरण हो जाने के बाद, कुछ विशिष्ट परिस्थितियों को छोड़कर एक उपहार को रद्द नहीं किया जा सकता है। (It was clarified that once possession is delivered, a gift cannot be revoked except under certain specific circumstances.)

## VIII. उत्तराधिकार (Inheritance)

\* अब्दुल हसन बनाम मलका (Abdul Hasan v. Malkah) (1938) 1 Cal 134

\* मुख्य मुद्दा (Key Issue): मुस्लिम उत्तराधिकार के सिद्धांत। (Principles of Muslim inheritance.)

\* निर्णय (Decision): यह मामला मुस्लिम कानून में उत्तराधिकार के सिद्धांतों को स्पष्ट करता है, जो सामान्यतः जन्म के अधिकार पर आधारित न होकर संपत्ति के स्वामित्व पर आधारित होते हैं। (This case clarifies the principles of inheritance in Muslim law, which are generally based on ownership of property rather than birthright.)

यहाँ मोहम्मद कानून के कुछ सबसे महत्वपूर्ण और अक्सर उद्धृत (cited) केस कानून दिए गए हैं, जो न्यायिक निर्णयों के माध्यम से मुस्लिम व्यक्तिगत कानून के विभिन्न पहलुओं को स्पष्ट करते हैं। ये विशेष रूप से विवाह, तलाक और भरण-पोषण से संबंधित हैं:

1. मोहम्मद अहमद खान बनाम शाह बानो बेगम (Mohd. Ahmed Khan v. Shah Bano Begum) (1985 AIR 945)

\* मुख्य मुद्दा (Key Issue): तलाकशुदा मुस्लिम महिला का भरण-पोषण का अधिकार। (Right to maintenance of a divorced Muslim woman.)

\* निर्णय (Decision): सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि एक तलाकशुदा मुस्लिम महिला आपराधिक प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 125 के तहत अपने पूर्व पति से भरण-पोषण का दावा कर सकती है, भले ही मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत 'इद्दत' की अवधि समाप्त हो गई हो। (The Supreme Court ruled that a divorced Muslim woman can claim maintenance from her former husband under Section 125 of the Criminal Procedure Code (CrPC), even after the 'iddat' period under Muslim Personal Law.)

2. डेनियल लतीफी बनाम भारत संघ (Danial Latifi v. Union of India) (AIR 2001 SC 3958)

\* मुख्य मुद्दा (Key Issue): मुस्लिम महिला (तलाक पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 1986 की संवैधानिकता और उसकी व्याख्या। (Constitutionality and interpretation of the Muslim Women (Protection of Rights on Divorce) Act, 1986.)

\* निर्णय (Decision): सुप्रीम कोर्ट ने 1986 के अधिनियम को संवैधानिक ठहराया, लेकिन यह स्पष्ट किया कि पति की जिम्मेदारी 'इद्दत' तक सीमित नहीं है। पति को इद्दत अवधि के दौरान और उसके बाद भी उचित और पर्याप्त भरण-पोषण देना होगा, जो उसके भविष्य की जरूरतों के लिए पर्याप्त हो। (The Supreme Court upheld the 1986 Act but clarified that the husband's liability is not limited to 'iddat'. He must provide fair and reasonable maintenance during and after the iddat period, sufficient for her future needs.)

3. शायरा बानो बनाम भारत संघ (Shayara Bano v. Union of India) (AIR 2017 SC 4609)

\* मुख्य मुद्दा (Key Issue): 'तीन तलाक' (तलाक-ए-बिद्दत) की संवैधानिक वैधता। (Constitutional validity of 'triple talaq' (talaq-e-biddat).)

\* निर्णय (Decision): सुप्रीम कोर्ट ने 'तीन तलाक' की प्रथा को असंवैधानिक घोषित किया, इसे मनमाना और कुरान के सिद्धांतों के विपरीत बताया। (The Supreme Court declared the practice of 'triple talaq' unconstitutional, terming it arbitrary and against the tenets of the Quran.)

4. शमीम आरा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (Shamim Ara v. State of Uttar Pradesh) (AIR 2002 SC 3550)

\* मुख्य मुद्दा (Key Issue): तलाक की घोषणा और उसके प्रमाण का तरीका। (Manner of pronouncement and proof of divorce.)

\* निर्णय (Decision): सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तलाक केवल पति द्वारा एकतरफा और मनमाने ढंग से घोषित करने से प्रभावी नहीं होता। तलाक वैध होने के लिए कुछ प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं, जैसे उचित कारण, सुलह के प्रयास और गवाहों का पालन किया जाना चाहिए। (The Supreme Court held that talaq does not become effective merely by an arbitrary and unilateral pronouncement by the husband. Certain procedural requirements, like a reasonable cause, attempts at reconciliation, and witnesses, must be followed for a valid talaq.)

5. नूर सबा खातून बनाम मोहम्मद कासिम (Noor Saba Khatoon v. Mohd. Quasim) (AIR 1997 SC 3280)

\* मुख्य मुद्दा (Key Issue): तलाकशुदा मुस्लिम महिला के बच्चों के भरण-पोषण का अधिकार। (Right to maintenance of children of a divorced Muslim woman.)

\* निर्णय (Decision): सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि एक मुस्लिम पिता आपराधिक प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 125 के तहत अपने नाबालिग बच्चों के भरण-पोषण के लिए उत्तरदायी है, भले ही बच्चों की मां को तलाक के बाद इद्दत अवधि के लिए भरण-पोषण मिल गया हो। (The Supreme Court clarified that a Muslim father is liable to maintain his minor children under Section 125 of the CrPC, even if the mother of the children has received maintenance for the iddat period after divorce.)